

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 552 दिनांक 18/02/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक एजेण्डा क्रमावार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों के तकनीकी परीक्षण किया गया ।

1. **Case No. 8308/2021 M/s. KJS Cement Ltd, NH-7 Road, Rajnagar, Maihar, Dist. Satna, MP - 485771 Prior Environment Clearance for Limestone Mine in an area of 23.230 ha. (Limestone - 560000 Tonne per annum, OB & Waste - 60000 Tonne per annum) (Khasra No. 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1033, 553, 554, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 624), Village - Bhadanpur South Patti, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) (In-Situ Enviro Care, Bhopal)**

This is case of Limestone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1033, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 624), Village - Bhadanpur South Patti, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 23.230 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 489th SEAC dated 12/03/2021 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

प्रकरण दिनांक 07/01/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हेतु प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहता है तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

आज दिनांक 18/2/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पुरानी खदान है जो चोपड़ा ब्रदर्स के नाम से 2004 में स्वीकृत हुई थी तत्पश्चात् 2005 में रामलाल दफ्तरी को स्थानांतरित हुई। रामलाल दफ्तरी से ये खदान के.जे.एस. सीमेंट को 2011 में स्थानांतरित हुई। यह खदान मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सी.टी.ओ. (पत्र क्रमांक 4635/टीएस/एमपीपीसीबी/माइन/14, दिनांक 30/07/14) के आधार पर 2014 तक कार्यशील रही एवं 2014 के बाद यह खदान बंद है। शासन के आदेश क्रमांक एफ-19-5/2015/12/1, दिनांक 12/3/15 के माध्यम से लीज अवधि दिनांक 01/02/2055 तक बढ़ाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में यह प्रावधानित किया गया कि ऐसे प्रकरण जो ई.आई. ए. नोटिफिकेशन 2006 के पूर्व से कार्यरत हैं को पर्यावरणीय स्वीकृति लीज नवीनीकरण के समय प्राप्त करनी होगी। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व के माइन ओनर द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किये जाने के कारण उन पर खनिज विभाग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था, वह भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा कर दिया गया है।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया कि वर्तमान स्थिति में खदान क्षेत्र के अंदर 03 माइंड आउटपिट स्थित है जिसमें पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 170 मीटर की दूरी पर तथा पूर्वी क्षेत्र में 110 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा एक कच्चा रोड़ खदान क्षेत्र से होकर निकल रहा है। इसी प्रकार उत्तर-पश्चिम दिशा में 136 मीटर पर पक्का रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित दोनों पिट एरिया में अधिकतम उत्खनन कार्य पूर्ण हो चुका है और वहाँ पर अब उत्खनन किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार उत्खनन दक्षिण दिशा वाले भाग में किया जाना प्रस्तावित है तथा खदान क्षेत्र से जो कच्चा रास्ता निकल रहा है वह खदान बंद होने के कारण ग्रामीणों द्वारा उपयोग किये जाने के कारण बन गया है। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि ग्रामीणों के आने-जाने के एक वैकल्पिक मार्ग उत्तर-पूर्वी दिशा में स्थित पिट-1 एवं पिट-2 के बीच से प्रस्तावित किया गया है जिसके चारों ओर सघन वृक्षारोपण भी किया जावेगा। पिट क्रमांक-3

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

जिसमें खनन् कार्य प्रस्तावित है के पानी को पिट क्रमांक-2 में पम्प किया जावेगा । खनन् कार्य के दौरान पिट क्रमांक-3 के आसपास 13 पेड़ों को काटा जावेगा तथा उसके एवज में 130 अतिरिक्त पेड़ों को लगाया जावेगा । समिति द्वारा काटे जाने वाले इवेंट्री के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि 13 में से एक पेड़ कुम्भी का है, जो विलुप्त प्रजाति का है अतः समिति ने यह निर्देशित किया कि जो अतिरिक्त 130 पेड़ लगाया जाना प्रस्तावित है, वे सभी कुम्भी प्रजाति के होने चाहिए ताकि इस प्रजाति को संरक्षित किया जा सके ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि प्रोजेक्ट साइट की गई वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के बहुत करीब है जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इसका मुख्य कारण खदान क्षेत्र पश्चिम दिशा में स्थित स्टोन केशर है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ शारदा पहाड़ी पर सघन वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र ।
- ✓ 130 कुम्भी प्रजाति के वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र ।
- ✓ पुनरीक्षित जल खपत योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 18/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन-5,00,000 टन/वर्ष एवं ओव्हर वर्डन - 60,000 टन/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 68.95 लाख एवं रिक्रिंग 07.77 लाख प्रति वर्ष ।

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 24.20 लाख :-

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1	Covid awarness program and disrtibution of mask, sanitizer and handwash and Oral hygine, Diabetes & Blood Pressure Awareness Acitivites in village Maheva.	1,00,000
2	Distruction of solar cooker and support under Ujjala scheme	1,70,000
3	Adoption of Bhadanpur Aganwadi for 5 years @2.00 Lakh /Year	10,00,000
4	Health Checkup camp at village Bhadanpur	2,00,000
5	Forestation of Sarda Hillock, Maihar with forest department	5,00,000
6	Drinking water supply through water tankers in summer season	1,00,000
7	Gate and maintainance of toilets of village school	3,50,000
	Total CER Cost	24,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 27,600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	कुम्भी, दूधी, हर्रा, वहेडा, खमार, चिरोल, जंगली जलेबी, जामुन, नीम, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	21,800
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, कुम्भी, चिरोल, जंगल जलेबी, करंज, नीम,, खमेर, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ट्री-गार्ड के साथ ।	4000
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1500
4	विद्यालय में	कदम, कचनार, करंज, हरसिगार, पुत्रांजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	300
		योग	27,600

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

2. Case No 8094/2021 Shri Rajesh Kaila, Sindhi Camp, PO & Dist. Satna, MP – 485001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.432 ha. (100000 Tonne per annum) (Khasra No. 649/2, 655, 656), Village - Bhatiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 649/2, 655, 656), Village - Bhatiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, (MP) 3.432 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 2009 dated: 14/10/2020 has reported that there are 04 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine total area of 15.378 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 477th SEAC dated 30/01/2021 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

आज दिनांक 18/2/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी दिशा में 165 मीटर जल संग्रहण क्षेत्र है तथा उत्तर-पूर्वी दिशा में 210 मीटर तथा पूर्व दिशा में 230 मीटर पर आबादी स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी वाले क्षेत्र के पास खदान में उत्खनन् रॉक-ब्रेकर से किया जायेगा तथा मफल ब्लास्टिंग की जावेगी । ब्लास्टिक होल की गहराई 03 मीटर से कम रखी जावेगी । प्रस्तुतीकरण के दौरान ज्ञात हुआ कि खदान क्षेत्र में लगभग 26 पेड़ हैं, जिसमें से 10 पेड़ काटे जायेंगे और उनके एवज में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि पूर्वी दिशा में 230 मीटर पर पक्का रोड़ है, जिसका उपयोग खनिज परिवहन हेतु किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 18/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,00,000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.30 लाख एवं रिकरिंग 05.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख :-

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1	Distruction of sport kits in School	20,000
2	Repraing of ground and roof top of school	30,000
3	Construction of 01 toilet in school	30,000
4	Drinking water supply during summer	45,000
5	Covid-19 activities and health chekup camp	25,000
6	Adoption of Aganwadi for poshanaahar	50,000
	Total CER Cost	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4220 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, सीताफल, खेर, चिरोल, करंज, अनोला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	970

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, नीम, खमेर, कचनार, अचार, शीशम, बेल, अमलतास, सीताफल, खेर, चिरोल, करंज, अनोला, देशी आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों, ट्री-गार्ड के साथ ।	3250
		योग	4220

3. Case No 8095/2021 Shri Rajesh Kaila, Sindhi Camp, PO & Dist. Satna, MP – 485001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.709 ha. (100000 Tonne per annum) (Khasra No. 654, 692, 674), Village - Bhatiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 654, 692, 674), Village - Bhatiya, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, (MP) 3.709 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 2010 dated: 14/10/2020 has reported that there are 05 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine total area of 15.501 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 477th SEAC dated 30/01/2021 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

आज दिनांक 18/2/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के पूर्वी दिशा में 120 मीटर जल संग्रहण क्षेत्र है तथा पूर्व दिशा में 200 मीटर पर आबादी स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी वाले क्षेत्र के पास खदान में उत्खनन् रॉक-ब्रेकर से किया जायेगा तथा मफल ब्लास्टिंग की जावेगी । ब्लास्टिक होल की गहराई 03 मीटर से कम रखी जावेगी । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि पूर्वी दिशा में 120 मीटर पर पक्का रोड़ है, जिसका उपयोग खनिज परिवहन हेतु किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान ज्ञात हुआ कि खदान क्षेत्र में लगभग ऑवले का 01 पेड़ है, जिसे काटा जायेगा और उनके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे ।

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 18/2/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,00,000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.20 लाख एवं रिक्रिंग 05.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख :-

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1	Distruction of sport kits in School	20,000
2	Repraing of ground and roof top of school	30,000
3	Construction of 01 toilet in school	30,000
4	Drinking water supply during summer	45,000
5	Covid-19 activities and health chekup camp	25,000
6	Adoption of Aganwadi for poshanaahar	50,000
	Total CER Cost	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4460 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, कचनार, शीशम, सीताफल, खेर, चिरोल, करंज, अनोला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1210
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, नीम, खमेर, कचनार, अचार, शीशम, बेल, अमलतास, सीताफल, खेर, चिरोल, करंज, अनोला, देशी आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ट्री-गार्ड के साथ ।	3250
		योग	4460

4. Case No 8885/2021 Shri Hari Singh Raghuvanshi, Owner, Manwani Colony, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (Stone - 10000 Cum per annum, Murrum - 6996 Cum per annum, Waste - 526 Cum per annum) (Khasra No. 1/1 Peki), Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

The case was presented by Consultant Shri Amit Saxena on behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office letter No. 3288 dated 07/12/21 has reported that there are 03 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 9.0 ha., including this mine.

The case was scheduled for the presentation in 542nd SEAC meeting dated 21/01/2022 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings.

आज दिनांक 18/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार ऑनलाईन उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 35 मीटर पर आई.टी.आई. पीथमपुर की बिल्डिंग एवं एक धर्मशाला स्थित है । यदि माननीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/7/20 (प्रकरण क्रमांक 304/19) के अनुसार निर्धारित 200 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाता है तो उत्खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा । समिति द्वारा सर्वसम्मति चर्चा कर यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण का पर्यावरणीय स्वीकृति उपयुक्त न होने से विचार नहीं किया जा सकता, अतः प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाये ।

5. Case No 6794/2020 Shri Santosh Nayak, Village - Gudali, Tehsil - Meghnagar, Dist. Jhabua, MP – 457772 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (24,832 cum per annum) (Khasra No. 68), Village - Tejpura, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 68), Village - Tejpura, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Tehsildar Office letter No. 690 dated: 28/06/19 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was scheduled for presentation, wherein neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the 426th SEAC meeting dated 27/2/2020 & 424th SEAC meeting dated 12/02/2020 and. Committee decided to call the PP in subsequent meetings giving last chance to present their case and even if PP remains absent the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was scheduled for presentation, but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in SEAC meeting 426th SEAC meeting dated 27/2/2020 & 424th SEAC meeting dated 12/02/2020. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was discussed in 651st SEIAA meeting dated 29/12/2020 and it has been recorded that.... *PP could not present the case in SEAC due to some unavoidable circumstances hence PP has submitted a request letter vide dated 14/12/2020 received in SEIAA office 15/12/2020 to relist the case as PP is now ready to present their case in SEAC. Considering the request of PP, it was decided to relist the case and send the technical file to SEAC for Appraisal.*

The case was scheduled in 477rd meeting dated 30/01/2021 for the presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation.

The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the 477rd meeting dated 30/01/2021. Committee decided to give last chance to PP for making presentation in the subsequent meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the SEAC 479th meeting dated 11/02/2021 SEAC & 477th meeting dated 30/01/2021. Committee decided to give last chance to PP for making presentation in the subsequent meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was scheduled for presentation, but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in the SEAC 479th meeting dated 11/02/2021 SEAC & 477th meeting

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

dated 30/01/2021. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 701वीं बैठक दिनांक 12/1/2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया कि :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 486वीं बैठक दिनांक 26/2/2021 में उक्त प्रकरण को डिलिस्ट किये जाने की अनुशंसा की गई है । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा एसईएसी की अनुशंसा को मान्य करते हुए 665वीं बैठक दिनांक 6/3/21 में उक्त प्रकरण *Delist* करने का निर्माण लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/12/21 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी में प्रस्तुतीकरण हेतु सहमति देते हुए उक्त प्रकरण को *Relist* करने को अनुरोध किया गया है ।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण को *Relist* किया जाये एवं प्रकरण परीक्षण हेतु एसईएसी को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाय।

The case was again schedule for presentation wherein committee observed that neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in SEAC meeting 426th SEAC meeting dated 27/2/2020 & 424th SEAC meeting dated 12/02/2020. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was again schedule for presentation wherein committee observed that PP was remains absent. Previously also PP remains absent several times when case was scheduled in agenda (refer SEAC previous meeting minutes). Considering above Committee observed that sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of his case but PP remains absent. Hence, committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project in the light of SEIAA recent letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/2. (According to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 - *SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR*).

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

6. Case No 8396/2021 Shri Lokesh Singh S/o Shri Babusingh Rajput, Village - Aslawada, Tehsil - Barnagar, Dist. Ujjain, MP - 459337 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Expansion from 5000 to 15000 cum per annum) (Khasra No. 259), Village - Kalmoda, Tehsil - Barnagar, Dist. Ujjain (MP).

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 259), Village - Kalmoda, Tehsil - Barnagar, Dist. Ujjain (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office (Ekal Praman-Patr) letter no. 1326 dated: 18/09/2018 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was presented by the PP and their consultant in the 494th SEAC meeting dated 31-03-21. wherein PP submitted that it is a case of expansion from 5,000 to 15,000 cum per annum and they have obtained compliance report of earlier EC conditions issued vide letter number 213 dated 15/03/21. During appraisal it was observed by the committee that three NCs are reported in compliance report by competent authority are as:

- Plantation 45/ha., was proposed whereas only 20 trees are at site.
- Under CER no record was found for social upliftment.
- No water supply permission was taken by PP.

After presentation PP was asked to submit detailed reply with firm commitment and time schedule for further consideration of this case.

During appraisal in 494 SEAC Meeting dated 31/03/21, it was observed by the committee that three NCs are reported in compliance report by competent authority.

After presentation PP was asked to submit detailed reply with firm commitment and time schedule for further consideration of this case PP's reply not received till date.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

Since the tenure of SEAC will be over on 09th April, 2021 and all such cases which are pending at SEAC will become category-I cases in the absence of SEAC. Thus case file is being sent to SEIAA for onward necessary action please.

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 701वीं बैठक दिनांक 12/1/2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 500वीं बैठक दिनांक 08/4/2021 में उक्त प्रकरण को डिलिस्ट किये जाने की अनुशंसा की गई है । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा एसईएसी की अनुशंसा को मान्य करते हुए 676वीं बैठक दिनांक 9/4/21 में उक्त प्रकरण *Delist* करने का निर्माण लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/12/21 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी में प्रस्तुतीकरण हेतु सहमति देते हुए उक्त प्रकरण को *Relist* करने को अनुरोध किया गया है ।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण को *Relist* किया जाये एवं प्रकरण परीक्षण हेतु एसईएसी को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाय ।

PP vide their letter dated 17/12/2021 uploaded online query reply on “Parivesh Portal”. and hard copy on dated 16.02.2022 wherein PP submitted that :

- PP has already ordered 200 plants from Malwa Nursery and expended Rs 2000/- and remaining amount will be paid after delivery of plant. Plantation Booking receipt has also attached.
- Mining operation has closed, when it will operational, We hereby committed that PP will expend Rs 60,000/- for Installation of 2000L overhead tank with proper water connectivity of Govt. Primary School, village Kalmoda and the same will be submitted with half yearly compliance report
- Water supply Permission letter issued by gram Panchayat is attached.

The submitted quarries were placed before the committee and the same found satisfactory. The EMP and other submissions made by the PP were found satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure ‘A’:

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Murrum 15,000 cum/annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.12.88 Lakh as capital and Rs. 07.66 Lakh/year.
3. As proposed, a minimum of 6000 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme.
4. Under CER following activities were submitted by PP:
 - Installation of 2000 liter capacity of overhead tank with proper connectivity at Govt. Primary school, Village, Kalmoda

7. Case No 7446/2020 Shri Hemendra Patel, Village - Jhabua, tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua, MP - 457661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 0.900 ha. (9522 cum per annum) (Khasra No. 519/1, 662/2), Village - Gadwadi & Devjhiri Panda, Tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 519/1, 662/2), Village - Gadwadi & Devjhiri Panda, Tehsil - Jhabua, Dist. Jhabua (MP) 0.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 791 dated: 26/05/2020 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was presented by the PP and their consultant in the in 453rd SEAC meeting dated 28-08-20. During presentation during presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, it was observed that the lease area is already excavated, at a glance seems it is a case of violation and PP has obtained CTO from MPPCB on 20.04.2014. Moreover, within 500 meters 03 other mine are in operation are seen while, Mining Officer reported that no mine within 500 meters hence, the committee asked PP to submit to revised MO certificate with justification regarding for excavated area.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

PP's reply not received till date and it appears that PP is not interested to continue with the project. Since the tenure of SEAC will be over on 09 October, 2020 and all such cases which are pending at SEAC will become category-I cases in the absence of SEAC. Thus case file is being sent to SEIAA for onward necessary action please.

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 701वीं बैठक दिनांक 12/1/2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 464वीं बैठक दिनांक 03/10/2020 में उक्त प्रकरण को डिलिस्ट किये जाने की अनुशंसा की गई है । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा एसईएसी की अनुशंसा को मान्य करते हुए 643वीं बैठक दिनांक 6/10/20 में उक्त प्रकरण *Delist* करने का निर्माण लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/12/21 एवं एसईआईएए कार्यालय में प्राप्त 20/12/21 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी में वांछित जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु सहमति देते हुए उक्त प्रकरण को *Relist* करने को अनुरोध किया गया है ।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण को *Relist* किया जाये एवं प्रकरण परीक्षण हेतु एसईएसी को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाय ।

PP vide their letter dated 01/02/2021 uploaded online query reply well as on "Parivesh Portal". Wherein PP submitted that:

- Lease renewal order is attached is attached.
- Justification regarding excavated area of the mine, As per Notification 7th October 2014 (copy attached), prior environmental clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal.
- Letter of mining officer stating that the mine site is included in the upcoming new DSR .
- The MO certificate of 500 m is attached.

The submitted quarries were placed before the committee and the same found satisfactory. The EMP and other submissions made by the PP were found satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Stone 9522 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.05.74 Lakh as capital and Rs. 03.13 Lakh/year.
3. As proposed, a minimum of 1200 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme .
4. Under CER following activities were submitted by PP:

Year	Detail	Amount in Lakh
01 Year	<ul style="list-style-type: none"> • 10 benches & tables for students of Govt. School, Gadwadi, Devjhiri Panda . • Water filter at Govt. School, Gadwadi, Devjhiri Panda . • Distribution of mask and sanitizer. • Development of grazing land in the identified village area . 	0.60
02 Year	<ul style="list-style-type: none"> • Toilets for school children with 02KL OH tanks. • Contribution for construction of boundary wall of primary school Gadwadi, 	1.20
	Total	1.80

8. Case No 7647/2020 Shri Kapil Pandey, Village - Rengua, Tehsil - Garhakota, Dist. Sagar, MP – 462008 Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.650 ha. (1500 cum per annum) (Khasra No. 347/1), Village - Bamnoda, Tehsil - Garhakota, Dist. Sagar (MP)

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 347/1), Village - Bamnoda, Tehsil - Garhakota, Dist. Sagar (MP) 1.650 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter No. 313 dated: 15/07/20 has reported that there is no more mine operating or proposed within 500 meters around the said mine.

The case was presented by PP and their consultant in 460th SEAC meeting dated 24/11/2020 wherein during appraisal it was observed by the committee that the mismatch

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

documents are submitted with case file. For example as per Form-2 submitted by PP and lease documents, the case is for Flagstone query while PFR, EMP submitted with case file, it is mentioned that the case is for Stone query. Moreover, in mine plan and PFR blasting is proposed and when committee asked RQP why blasting is required in case of flagstone production, no satisfactory answer was provided by him. Thus committee after deliberation decided that case file may be sent to SEIAA and PP may be asked to resubmit the case file after making necessary corrections in the submitted documents.

SEIAA in their 646th meeting dated 28/11/20 decided that case file may be sent to SEAC as PP has submitted an affidavit that no blasting will be carried out and sent the file vide letter no. 5104 dated 09/12/20.

The case was scheduled for the presentation in 470th SEAC meeting dated 18/12/2020 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings.

The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the 472nd SEAC meeting dated 6/1/2021 & 470th SEAC meeting dated 18/12/2020. Committee decided to give last chance to PP for making presentation in the subsequent meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

The case was scheduled for presentation, but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in 472nd SEAC meeting dated 6/1/2021 & 470th SEAC meeting dated 18/12/2020. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

The case was discussed in 693th SEIAA meeting dated 25/11/2021 , it was recorded that..

The case was discussed in 658th SEIAA meeting dated 09/2/2021 & it was recorded that.. This case was recommended in 476th SEAC meeting dated 29/01/2021 and it was recorded that.

The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the 472nd SEAC meeting dated 6/1/2021 & 470th SEAC meeting dated 18/12/2020. Committee decided to give last chance to PP for making presentation in the subsequent meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.

As per above observation of SEAC, it has been decided to delist the case on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal.

PP has submitted required documents vide letter dated 26/10/21 received in SEIAA Office on 26/10/2021 and requested to relist the case by showing interest to present their case in SEAC. Considering the request of PP, it was decided to relist the case and technical file send to SEAC for appraisal.

The case was discussed in 693rd SEIAA meeting dated 09/02/2021 & it was recorded that. This case was recommended in 476th SEAC meeting dated 29/01/2021 and it was recorded that.

The case was scheduled for presentation, but neither the project proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be reised of to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in 472nd SEAC meeting dated 06/1/2021 & 470th SEAC meeting dated 18/12/2020. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assumring that PP is not interested to continue with the project.

As per above observationof SEAC, it has been decided to delist the case on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

PP has submitted required documents vide letter dated 26/10/21 received in SEIAA Office on 26/10.2021 and requestd to relist the case by showing interest to present their case in SEAC. Considering the request of PP, it was decided to relist the case and technical file send to SEAC for appraisal.

The case was scheduled for the presentation in 541st SEAC meeting dated 20/01/2022 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings.

In this meeting the case was schedule for query reply presentation wherein PP submitted that they have submitted approved modified Mining Plan of Flag Stone which has approved by Regional Head, DGM, R.O. Jabalpur vide no. 8921-22 dated 15-09-2021 for the period from 2021- 2022 to 2024-25. PP submitted that since it is a Flagstone Quarry, no blasting and drilling is proposed. Mining shall be through Opencast Semi Mechanized Method. As per Google image based on online KML file uploaded by PP, it was observed that a kachha road is existing in the west side of the lease at a distance of 70 m .

The query reply was discussed with PP and their consultant and the submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence committee after deliberation found that the EMS and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Flag Stone 1500 Cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 05.0 Lakh as capital and Rs. 01.98 Lakh/year.
3. As proposed, a minimum of 1900 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme.
4. Under CER activity, following activities are proposed based public hearing issues.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

S.No.	FOR SOCIAL WELFARE:	Amount to be spent
1.	Proposal of Playground development , Taffic awareness acamp , Solar Light , COVID-19, in the BelaiGhat	50,000.00
2	Devlopment of grazing land in the identified village area .	10,000.00
Total		60,000.00

9. Case No 8877/2021 Shri Ashok Patidar, Village - Khokrakalan C/o Village - Chakranabad, Tehsil - Kalapipal, Dlst. Shajapur, MP - 465337 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5000 Cum per annum) (Khasra No. 25/16), Village - Chakranabad, Tehsil - Kalapipal, Dist. Shajapur (MP) RQP Swati Namdeo

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 25/16), Village - Chakranabad, Tehsil - Kalapipal, Dist. Shajapur (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was scheduled for the presentation in 540th SEAC meeting dated 08/01/2022 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings.

The case was presented by RQP Swati Namdeo behalf of PP. During presentation as per Google image based on online KML file uploaded by PP, it was observed that habitation is adjacent to the lease area and if 200 m area is left then no mineable area shall be left. hence, Committee deliberated that as per NGT order dated 21/07/2020 in OA no. 304/2019, minimum 200 meters distance is to be maintained from inhabited area and if this distance is left, the lease becomes non minable. Considering above facts, committee

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

after deliberation recommends that this case cannot be considered for grant EC and file may be sent to SEIAA for onward necessary action.

10. Case No 8833/2021 M/s Maa Narbada Crusher, Proprietor, Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha. (8858 Cum per annum) (Khasra No. 46/1 Peki), Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 46/1 Peki), Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) 2.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was scheduled for the presentation in 534th SEAC meeting dated 15/12/2021 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Committee decided to call the PP in subsequent meetings.

The case was presented by Consultant Shri Amit Saxena on behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR, EMP & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekle Praman-patra) letter No. 3117 dated 11/11/2021 has reported that there are 03 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 10.9 ha. including this mine.

Being it's a case Stone Quarry with total area of 10.90 ha. as per Google image based on online KML file uploaded by PP it was observed that the allotted lease area is already mined out without obtaining EC hence, indicates violation of EIA Notification, 2006. Committee after deliberation recommends that under above circumstances where proposed lease area is already mined out this case cannot be considered for grant of EC and case file may be sent to SEIAA for onward necessary action.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

DISCUSSION BASED ON QUERY REPLY SUBMITTED BY PP/ PENDING SINCE LONG

11. Case No 7944/2020 Shri Dilip Koushal S/o Shri Lekhram Koushal, Ward No. 5, Gomukh Road, Khirkiya, Dist. Harda Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.547 ha. (11,878 cum per annum) (Khasra No. 555/1), Village - Choukadi, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 555/1), Village - Choukadi, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP) 1.547 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 129 dated: 23/5/2020 has reported that there are 05 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 18.097 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 469th SEAC dated 17/12/2020 wherein ToR was recommended.

PP and their consultant presented the EIA before the committee in the 504th SEAC meeting dated 23.07.2021 and after presentation committee asked PP to submit response on following issues including irrelevant/misleading information provided in From-II.

PP vide their letter dated 07/08/2021 submitted query reply hard copy as well as on Ministry's Parivesh Portal. The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC (in the 511th SEAC meeting dated 26/08/2021) .

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Stone 11,878 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 16.075 Lakh as capital and Rs. 4.70 Lakh/year as recurring has proposed by PP.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

3. As proposed, a minimum of 1066 trees /year shall be planted within three years in barrier zone, evacuation road, and village through local DFO or Gram Panchayat etc. as per the submitted plantation scheme.
4. All plantation in village shall be uploaded on “Vayudoot app” under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers .

The case was discussed in 685th Meeting of SEIAA dated 14/9/21 hence case along with technical file sent to SEAC for re-appraisal on following shortcomings.

- All issues raised during the public hearing should be checked properly in respect of all three sanctioned lease (Case no. 7945 and 7946) included in the cluster have to be clubbed & replied together, and address in EC condition.
- In such case details of mine owned or being operated by the same owner should be collected and compliance to EC/MPPCB consent conditions shall be reviewed.
- Details of Land ownership/agreement and consent with private land owner shall also be reviewed.

In the SEAC 522nd meeting dated 27.10.2021 the case was scheduled for PP reply w.r.t. concern raised by SEIAA in the 685th Meeting dated 14/9/21. The matter was discussed wherein PP submitted that following points are as :

- Issues Raised by local villagers during the public hearing should be checked properly and shall be addressed under EC Conditions. PP replied, issues raised by local villagers during the public hearing are checked properly and addressed in EIA/EMP reports (Refer to page no. 116 to 122 of EIA report) and PH was conducted separately by Regional Office, MPPCB on same day at different time, that's why we had considered separate public hearing proceeding for each case. PH Minutes also attached as Annexure-1.
- In such cases details of mines owned or being operated by the same owner should be collected and compliance shall also be reviewed. Same owner has one more operational mine.
PP replied that the compliance of EC conditions (case no. 3438) has already been submitted by PP. (Annexure-2)
- Details of Land ownership/agreement and consent with private land owner shall also be reviewed. PP replied that PP has the land ownership of this mine (Khasra no. 555/1) Khasra Panchshala is attached .

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

Hence the committee after deliberations decided to stand by its earlier recommendation made in 511th SEAC meeting dated 26-08-21.

The case was discussed in 693th SEIAA meeting dated 25/11/2021 and case file sent to SEAC for re-appraisal.

In the SEAC 538th meeting dated 06.01.2022 the case was scheduled for query presentation in the light of case send to SEAC for re-appraisal by SEIAA in 693rd meeting dated 25-11-21. The reply was presented Env. Consultant Shri Amar Singh Yadav from M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow, U.P on behalf of PP. During presentation committee observed that in the online Form-II and other submissions in the EIA report have not correctly matched with the mentioned points/information.

In this meeting the case was again scheduled for query reply presentation wherein PP submitted following points:

- Case send to SEAC for re-appraisal in 693 SEIAA meeting dated 25-11-21. Letter no. 2620-21/SEIAA/21 dated 17-12-21 along with technical file to SEAC.
- This is a new lease sanctioned vide letter no. Issued vide letter no. Issued vide letter no. 2464/ Mineral/s.no. 3/2018-19, Harda Dated: 28.02.2019, bearing Khasra no. 555/1 of 1.547 ha.
- However, 01 other mine is in existence of same PP (Shri Dilip Koushal) under operation since 2015 in which EC Letter is issued by SEIAA LetterNo.7917/SEIAA/2015. This mine is not going to expand its lease area or not going to increase the production.
- Also, 01 other mine (Case. No. 7945) is new and has been applied for obtaining EC from SEIAA.
- As per EIA notification 2006, “Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization”. Thus both mines are separate projects and in this condition the new mine should not be considered as a case of an expansion of old mine.
- Compliance report of existing mine has been updated in MPSEIA web Site.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

Hence, the committee after discussion deliberated that this case should not be treated as a case of expansion and committee stand by earlier recommendation made in the 511th SEAC meeting dated 26/08/2021.

12. Case No 7945/2020 Shri Dilip Koushal S/o Shri Lekhram Koushal, Ward No. 5, Gomukh Road, Khirkiya, Dist. Harda, MP - 461331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.558 ha. (11,878 cum per annum) (Khasra No. 555/3), Village - Choukadi, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 555/3), Village - Choukadi, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP) 1.558 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 130 dated: 23/5/2020 has reported that there are 05 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 18.102 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 469th SEAC dated 17/12/2020 wherein ToR was recommended.

PP and their consultant presented the EIA before the committee in the 504th SEAC meeting dated 23.07.2021. After presentation committee asked PP to submit response on following issues including irrelevant/misleading information provided in From-II, .

PP vide their letter dated 07/08/2021 submitted query reply hard copy as well as on Ministry's Parivesh Portal. The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC (in the 511th SEAC meeting dated 26/08/2021) subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Stone 11,878 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 16.034 Lakh as capital and Rs. 4.66 Lakh/year as recurring has proposed by PP.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

3. As proposed, a minimum of 1000 trees /year shall be planted within three years in barrier zone, evacuation road, and village through local DFO or Gram Panchayat etc. as per the submitted plantation scheme.
4. All plantation in village shall be uploaded on “Vayudoot app” under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers .

The case was discussed in 685th Meeting of SEIAA dated 14/9/21 hence case along with technical file sent to SEAC for re-appraisal on following shortcomings.

- The Khasra number and Name of PP in the attached Quality Test Report (Air, Water, Soil and Noise) is different than that of the proposed mine as part of EIA report prepared and submitted by the consultant authorizes by PP.
- All issues raised during the public hearing should be checked properly in respect of all three sanctioned lease (Case no. 7944 and 7946) included in the cluster have to be clubbed & replied together, and address in EC condition.
- In such case details of mine owned or being operated by the same owner should be collected and compliance to EC/MPPCB consent conditions shall be reviewed.
- Details of Land ownership/agreement and consent with private land owner shall also be reviewed context to above it is decided to send the case along with technical file to SEAC for re-appraisal.

In the 522nd SEAC meeting dated 27-10-21 the case was scheduled for query reply presentation w.r.t. concern raised by SEIAA in the 685th Meeting dated 14/9/21. The matter was discussed wherein PP submitted points-wise query reply.

Hence the committee after deliberations decided to stand by its earlier recommendation made in 511th SEAC meeting dated 26-08-21.

The case was discussed in 693th SEIAA meeting dated 25/11/2021 the case along with technical file sent to SEAC for re-appraisal.

In the SEAC 538th meeting dated 06.01.2022 the case was scheduled for query presentation in the light of case send to SEAC for re-appraisal by SEIAA in 693rd meeting dated 25-11-21. The reply was presented Env. Consultant Shri Amar Singh Yadav from M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow, U.P on behalf of PP. During presentation committee observed that in the online Form-II and other submissions in the EIA report have not correctly matched with the mentioned

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

points/information. During presentation committee observed that in the online Form-II and other submissions in the EIA report have not correctly matched with the mentioned points/information.

In this meeting the case was again scheduled for query reply presentation wherein PP submitted following points:

- Case send to SEAC for re-appraisal in 693 SEIAA meeting dated 25-11-21. Letter no. 2610-11/SEIAA/21 dated 17-12-21 along with technical file to SEAC - for re-appraisal.
- This is a new lease sanctioned vide letter no. Issued vide letter no. Issued vide letter no. 2466/ Mineral/s.no. 2/2018-19, Harda Dated: 28.02.2019, bearing Khasra no. 555/3 of 1.558 ha.
- However, 01 other mine which is in existence is of same PP is under operation since 2015 in which EC Letter was issued by SEIAA vide Letter No. 7917/SEIAA/2015. This mine is not going to expand its lease area or not going to increase the production.
- Also, 01 other mine (Case no. 7944) is new and has been applied in SEIAA in obtaining for EC (Under process).
- As per EIA notification 2006, “Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization”.
- Thus both mines are separate projects and in this condition the new mine should not be considered as a case of an expansion of old mine.
- Compliance report of existing mine has been updated in MPSEIA web Site.

Hence, the committee after discussion deliberated that this case should not be treated as a case of expansion and committee stand by earlier recommendation made in the 511th SEAC meeting dated 26/08/2021.

13. Case No 7946/2020 Shri Malkhan Singh S/o Shri Sangram Singh, R/o Gambhir Road, Khedipura, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda, MP - 461441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (22,148 cum per annum) (Khasra No. 509), Village - Choukadi, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Noida U.P.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 509), Village - Choukadi, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP) 3.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 1121 dated: 06/10/2020 has reported that there are 04 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 13.997 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 469th SEAC dated 17/12/2020 wherein ToR was recommended.

PP and their consultant presented the EIA before the committee in the 504th SEAC meeting dated 23.07.2021. After presentation committee asked PP to submit response on following issues including irrelevant/misleading information provided in From-II.

PP vide their letter dated 06/08/2021 submitted query reply hard copy as well as on Ministry's Parivesh Portal. The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC (in the 511th SEAC meeting dated 26/08/2021).

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Stone 22,148 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs. 12.55 Lakh as capital and Rs. 5.55 Lakh/year as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 1200 trees /year shall be planted within three years in barrier zone, evacuation road, and village through local DFO or Gram Panchayat etc. as per the submitted plantation scheme.
4. All plantation in village shall be uploaded on "Vayudoot app" under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers .

The case was discussed in 685th Meeting of SEIAA dated 14/9/21 hence case along with technical file sent to SEAC for re-appraisal on following shortcomings.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

- The Khasra number and Name of PP in the attached Quality Test Report (Air, Water, Soil and Noise) is different than that of proposed mine as part of EIA report prepared and submitted by the consultant authorizes by PP.
- All issues raised during the public hearing should be checked properly in respect of all three sanctioned lease (Case no. 7944 and 7945) included in the cluster have to be clubbed & replied together and address in EC condition.
- In such case details of mine owned or being operated by the same owner should be collected and compliance to EC/MPPCB consent conditions shall be reviewed.
- Details of Land ownership/agreement and consent with private land owner shall also be reviewed.

In this meeting SEAC 522 dated 27.10.21 the case was scheduled for PP reply w.r.t. concern raised by SEIAA in the 685th Meeting dated 14/9/21.

Hence the committee after deliberations decided to stand by its earlier recommendation made in 511th SEAC meeting dated 26-08-21.

The case was discussed in 693th SEIAA meeting dated 25/11/2021 and case along with technical file to SEAC for re-appraisal.

In the SEAC 538th meeting dated 06.07.2022 the case was scheduled for query presentation in the light of case send to SEAC for re-appraisal by SEIAA in 693rd meeting dated 25-11-21. During presentation committee observed that in the online Form-II and other submissions in the EIA report have not correctly matched with the mentioned points/information. During presentation committee observed that in the online Form-II and other submissions in the EIA report have not correctly matched with the mentioned points/information.

In this meeting the case was again scheduled for query reply presentation wherein PP submitted following points:

- Letter no. 2618-19/SEIAA/21 dated 17-12-21 along with technical file to SEAC.
- This is a new lease sanctioned vide letter no. 5933/ Mineral/s.no. 2/2020, Bhopal Dated: 04.07.2020, bearing Khasra no. 509 Part of 3.00ha.
- However, other mine which is in existence is of same PP and under operation since 2015 for which EC Letter Issued by SEIAA Letter No. 7911/SEIAA/2015,

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

Dated 19.11.2015. This mine is not going to expand its lease area or not going to increase the production.

- As per EIA notification 2006, “Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization”.
- Thus both mines are separate projects and in this condition the new mine should not be considered as a case of an expansion of old mine.
- Compliance report of existing mine has been updated in MPSEIAA web Site.

Hence, the committee after discussion deliberated that this case should not be treated as a case of expansion and committee stand by earlier recommendation made in the 511th SEAC meeting dated 26/08/2021.

14. Case No 8748/2021 Shri Naresh Dhakad S/o Shri Girvarlal Dhakad, 145, M.S. Road, Infront of Block Office, Ward No. 02, Tehsil - Joura, Dist. Morena, MP - 476221 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (Gitti - 10000 cum per annum, Khanda - 3037 cum per annum) (Khasra No. 2667), Village - Parsota, Tehsil - Joura, Dist. Morena (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2667), Village - Parsota, Tehsil - Joura, Dist. Morena (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Ram Milan Pathak on behalf of PP in the 525th SEAC meeting dated 10-11-21. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR, EMP & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office letter No. 894 dated 19.07.2021 has reported that there is 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 5.0 ha., including this mine. As per Google image based on online KML file uploaded by PP, around 500 meters following sensitive features were observed of the lease area:

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

Sensitive Features	Approximate aerial distance from the lease area in meters	Direction	Remarks
Canal	290	North	Provision of Garland drain & settling tanks.
Human settlement	800 820	SW E	Controlled blasting with arrangements of sand bags and three rows of Plantation towards road side..
Seasonal Drain	90	South –East	Provision of Garland drain & settling tanks.

presentation the committee asked to submit following details:

- Legible copy of DSR.
- Revised Plantation scheme as suggested by committee with proposal for sowing of Safed Castor and Neem seeds along the barrier zone.
- Propose at least plantation of 50 medicinal plants in the Medicinal plant garden (viz. shrubs, creepers or any other locally available species) as suggested by committee.
- Revised EMP & CER as suggested by committee.

PP has submitted the response of above quarries same date vide letter dated 10.11.2021, which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee after deliberation found that The EMS and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Stone (Gitti and Khanda) – 12,667 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.16.22 Lakh as capital and Rs. 04.79 Lakh/year.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

3. As proposed, a minimum of 2400 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme and under CSR Rs. 01.02 Lakh/years is proposed.

Vide SEIAA's letter no. 2981/SEIAA/21 dated 04.02.2022, enclosing an e-mail received from PP was sent to SEAC, wherein PP has addressed SEIAA query regarding detailed environment management plan (EMP) by NABET approved consultant within 30 days to this office.

Hence, this case was scheduled for presentation wherein it was observed PP has submitted detailed environment management plan (EMP) approved by NABET consultant along with incorporating suggestion given by residents within 500 m . The committee after discussion deliberated that PP has submitted desired document by SEIAA hence stand by earlier recommendation made in the 525th SEAC meeting dated 10/11/2021.

15. Case No 8747/2021 Shri Subhash Dhakad S/o Shri Naresh Dhakad, Ward No. 02, M.S. Road, Infront of Joura Block, Tehsil - Joura, Dist. Morena, MP - 476221 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (Gitti - 10104 cum per annum, Khanda - 2694 cum per annum) (Khasra No. 3016, 3022), Village - Parsota, Tehsil - Joura, Dist. Morena (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3016, 3022), Village - Parsota, Tehsil - Joura, Dist. Morena (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Ram Milan Pathak on behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR, EMP & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office letter No. 895 dated 1907.2021 has reported that there is 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 5.0 ha., including this mine. As per Google image based on online KML file uploaded by PP, it was observed that the a pit is in existence within the lease for which PP submitted that it's an old pit which is shown in the surface map attached

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

with the mine plan approved by the competent authority. Around 500 meters following sensitive features were observed of the lease area:

Sensitive Features	Approximate aerial distance from the lease area in meters	Direction	Remarks
Canal	320	North	Provision of Garland drain & settling tanks.
Human settlement	275	SW	Controlled blasting with arrangements of sand bags and three rows of Plantation towards road side..

presentation the committee asked to submit following details:

- Legible copy of DSR.
- Revised Plantation scheme as suggested by committee with proposal for sowing of Safed Castor and Neem seeds along the barrier zone.
- Propose at least plantation of 50 medicinal plants in the Medicinal plant garden (viz. shrubs, creepers or any other locally available species) as suggested by committee.
- Revised EMP & CER as suggested by committee.

PP has submitted the response of above quarries same date vide letter dated 10.11.2021, which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee after deliberation found that The EMS and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Stone (Gitti – & Khanda) – 12,798 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.16.95 Lakh as capital and Rs. 05.72 Lakh/year.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2022

3. As proposed, a minimum of 3600 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme and under CSR Rs. 0.975 Lakh/years is proposed.

Vide SEIAA's letter no. 2982/SEIAA/21 dated 04.02.2022, enclosing an e-mail received from PP was sent to SEAC, wherein PP has addressed SEIAA query regarding detailed environment management plan (EMP) by NABET approved consultant within 30 days to this office.

Hence, this case was scheduled for presentation wherein it was observed PP has submitted detailed environment management plan (EMP) approved by NABET consultant along with incorporating suggestion given by residents within 500 m . The committee after discussion deliberated that PP has submitted desired document by SEIAA hence stand by earlier recommendation made in the 525th SEAC meeting dated 10/11/2021.

(A. A. Mishra)
Secretary

(Dr. Praveen Chandra Dubey)
Chairman

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khush Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

552वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2022

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.